शुगर इंडस्ट्री को 1,000 करोड़ का होगा लॉस

गन्ने और शुगर की कीमतों में अंतर बढ़ने से होगा नुकसान

[पीटीआई *नई दिल्ली*]

मार्केटिंग ईयर 2012-13 में शुगर इंडस्ट्री को 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लॉस की आशंका है। क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से इंडस्ट्री को यह नुकसान हो सकता है। यह मार्केटिंग ईयर इस साल सितंबर में खत्म होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि गन्ने की कीमत में सालाना जहां सिर्फ 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, वहीं मार्केटिंग ईयर 2010-11 और 2012-13 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान चीनी के दाम महज 3 फीसदी बढ़े।

रिपोर्ट के मुताबिक, गन्ने और शुगर की कीमतों में अंतर बढ़ने से शुगर सीजन 2012-13 में इंडियन इंडस्ट्री का नेट लॉस 1,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। क्रिसिल का कहना है कि अगले मार्केटिंग ईयर में हालात और खराब हो सकते हैं।

शुगर सीजन 2013-14 के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने के मिनिमम प्राइस में 24 फीसदी बढ़ोतरी का एलान किया है, जबकि क्रिसिल के मुताबिक शुगर की कीमत में इस दौरान सिर्फ 8-9 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसलिए शुगर मिलों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब होगा।

सबसे बुरा असर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की मिलों पर पड़ सकता है, जहां राज्य सरकारें गन्ने के लिए स्टेट एडवाइज्ड प्राइस (एसएपी) का एलान करती हैं। यह केंद्र के फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) से ज्यादा होता है। क्रिसिल का कहना है कि शुगर में इनपुट कॉस्ट के मुकाबले काफी कम बढ़ोतरी का असर उन 74 कंपनियों की बैलेंसशीट पर भी देखने को मिला है, जिनकी एनालिसिस रिसर्च फर्म ने की है।

रिसर्च फर्म ने सलाह दी है कि गन्ने की कीमत को शुगर और दूसरे बाय-प्रोडक्ट्स से लिंक किया जाना चाहिए। शुगर सेक्टर डीकंट्रोल पर बनी रंगराजन कमेटी ने ऐसी ही सिफारिश की थी। क्रिसिल के रिसर्च डायरेक्टर (इंडस्ट्री रिसर्च) अजय श्रीनिवासन ने बताया, 'मार्केटिंग ईयर 2012-13 तक पिछले तीन सीजन में शुगर और इसके बाय-प्रोडक्ट्स की सेल में गन्ने की लागत की हिस्सेदारी बढ़कर 76-79 फीसदी हो गई है, जबकि पिछले दशक में यह एवरेज 67 फीसदी थी। इससे कई मिलें नुकसान में चल रही हैं।'

- **गन्ने की** कीमत में सालाना जहां सिर्फ 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, वहीं मार्केटिंग ईयर 2010-11 और 2012-13 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान चीनी के दाम महज 3 फीसदी बढ़े
- शुगर के दाम में सिर्फ 8-9 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसलिए मिलों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब होगा

इकनॉमिक टाइम्स

14/6/13